बातचीत के बिंदु-06

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

निजीकरण

नरेंद्र मोदी सरकार 'राष्ट्रवादी' और 'देशभक्ति' होने का दावा करती है लेकिन इसने राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्तियों को निजी उद्योगपतियों कोबेचने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अपने शासन के चार वर्षों में, उसने 1.96 लाख करोड़ रुपये की सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पत्तियों को बेचा है।

लेकिन इतना भर ही नहीं है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के नाम पर वे खनिज संसाधन, भूमि, नदियों और झीलों, जंगलों और यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को भी निजी कंपनियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा उत्पादन से लेकर तेल उत्पादन तक, दवाओं से स्कूली शिक्षा तक –सब कुछ,लाभ बनाने वाले निजी स्वामित्व के उद्यम मेंतेजी से बदल रहा है। निजी कॉरपोरेट वर्ग की मदद करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी है कि तथाकथित 'रखरखाव' के लिए भी ऐतिहासिक स्मारकों को कंपनियों को सौंपा जा रहा है! इससे पहले कभी भी किसी भी देश ने 'राष्ट्रवाद' और 'मातृभूमि' की इतनी ज्यादा बातें,और साथ ही शर्मनाक ढंग से देशी–विदेशी मुनाफाखोरों के हाथों में उसी मातृभूमि की बिक्री नहीं देखी है।

यह निजीकरण का अभियान भारत के मजदूरों, विशेष रूप से युवा मजदूरों को वस्तु के रूप में पेश कर रहा है, जो मुनाफों के भूखेकॉरपोरेटस् के लिए सस्ते में उपलब्ध हैं। अपने 'मेक इन इंडिया' विश्व भ्रमण के माध्यम से, मोदी और उनके मंत्रीगण वैश्विक पूँजीपतियों को भारत में निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सस्ता भारतीय श्रम उनके मुनाफे को भारी बढ़ावा देंगे!

सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री

सस्ती कीमतों परसार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना सभी नव उदारवादी व्यवस्थाओं की चिरपरिचित नीति है। पिछली कॉंग्रेसनीत यूपीए सरकार ने अपने दस साल के शासन में 1.08 लाख करोड़ रुपये की सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पत्तियों को बेच दिया था। लेकिन इस नीति को मोदी सरकार द्वारा एक नए स्तर पर ले जाया गया है। कॉंग्रेस ने जो 10 वर्षों में किया,इसने उससे कहीं ज्यादा 4 सालों में कर डाला।

सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक, 12.3 लाख से ज्यादा कामगारों को रोजगार वाले भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सकल संपत्तियां हैं और 2015–16 में 7095 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभांश घोषित किया गया है। वे देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए एक कवच हैं। इन उद्यमों द्वारा उत्पन्न लाभ, सरकार द्वारा सार्वजनिक हितलाभ के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक बार उनके निजी हो जाने के बाद, सारे लाभ बड़े कॉरपोरेटस् की जेबोंके हवाले हो जाएंगे।

इन उद्यमों के अलावा, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के शेयर भी बेच रही है जो करीब 15 लाख कर्मचारियों को रोजगार देते हैं। इस तरह से कमजोर करते रहना केवल विदेशी कंपनियों को अत्यधिक लाभकारी सरकारी कंपनियों के शेयरों को कब्जाने की अनुमति देगा। इससे नौकरियों को भी नुकसान हो जाऐगा। यह पहले यूपीए सरकार के तहत दी गयी, निजी (विदेशी) बैंकों और बीमा कंपनियों को देश में संचालित करने की अनुमति के अतिरिक्त है।

सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों (या सीधे बिक्री) को बेचने से देश की जनता पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। इसका मतलब है कि निजी कंपनियाँ अपने द्वारा अधिकृत औद्योगिक इकाइयों के संचालन के माध्यम से लाभ को चूसने लगती हैं। अब तक, ये इकाइयाँ अपनी कमाई के माध्यम से देश के अच्छे के लिए योगदान दे रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निजी कॉरपोरेटस्अपनी जेबें भरने से अधिक कुछ नहीं करेंगे।

लेकिन इससे और भी अधिक है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को स्थापित किया गया था क्योंकि देश की संप्रभुता को संरक्षित करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, क्या आप विदेशी कंपनियों के सहयोग से रिलायंस जैसी निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन में घुसने की अनुमति दे सकते हैं? क्या यह देश की आजादी और आत्मनिर्भरता को खतरे में नहीं डाल देगा?

फिर रोजगार और अन्य सार्वजनिक नीति की जरूरतों का सवाल महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्र न केवल बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है बल्कि निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ भी प्रदान करता है। यह एससी/एसटी के आरक्षण के लिए संवैधानिक जनादेश का भी पालन करता है। ईकाई का निजीकरण होने के बाद यह सब कुछ खिड़की से बाहर हो जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश के लिए कोई वास्तविक आर्थिक या प्रबंधन संबंधित कारण नहीं है। तो मोदीनीत बीजेपी सरकार का इसके प्रति झुकाव क्यों है? जवाब दुहरा है। एक, सरकार को बहुत पैसा मिलता है जिससे वह अपने खजाने को बढ़ा सकती है। यह सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है क्योंकि यह स्वस्थ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, या नौकरियां पैदा करने में असमर्थ है। कृषि में संकट जारी है। नोटबन्दी और जीएसटी जैसी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को और बर्बाद कर दिया है। बीजेपीनीत मोदी सरकार सोचती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री से राजस्व पैदा करके यह पूरे दौर के संकट से जूझ सकती है।

दूसरे, मोदी सरकार बड़े उद्योगपति तबके की भलाई और समृद्धि के प्रतिशर्मनाक तरीके से प्रतिबद्ध है – चाहे वह देशी या विदेशी हो। प्रधानमंत्री गरीबों के कल्याण के बारे में अनेक बातें बोल रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार के कृत्यों का उद्देश्य कॉरपोरेटस् की सेवा के लिए गरीबों को लूटना है। इन कॉरपोरेटस् घरानों को लाभ बनाने के लिए, वह जन सम्पत्ति के बड़े हिस्से को सौंप रहा है, जिसे सार्वजनिक धन के माध्यम से वर्षों में बनाया गया। 'राष्ट्रवाद' और 'देशभक्ति' का राग आम जनता को बरगलाने के लिए हैं, ताकि वे सरकार के कारण होने वाले सभी संकटों को भूल जाएं।

प्राकृतिक संसाधन

यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नहीं हैं जिन्हें निजी हाथों में बेचा जा रहा है। देश में चारों ओर एक नजर डालने से पता चलता है कि जो कुछ भी सरकारी है,–या सरकार द्वारा चलाना चाहिए –वह सब कुछ बिक्री के लिए तैयार है। पानी से लेकर खनिज संसाधनों तक, सड़कों और पुलों से बंदरगाहों और गोदी तक, स्कूलों और कॉलेजों से अस्पतालों और दवाइयों तक, जो कुछ भी हाल ही में एक सरकारी होना चाहिए उसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया जा रहा है।

मोदी सरकार ने देश के अनेक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का निजीकरण करने के कदम बढ़ाऐ हैं जिसमें लौहएवं गैर–लौह खनिज, कोयला, तेल और गैस, जंगलों, जल निकायों और जल विद्युत उत्पादन सहित विद्युत उत्पादन शामिल हैं। कोल इंडिया और नेशनल हाइड्रो–पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) जैसे

सार्वजनिक क्षेत्र के भारी लाभ कमाने वाले निकायों को निजीकरण द्वारा निचोड़ा जा रहा है। कोयला खदानों के स्वामित्व और दोहन करने की इजाजत लालची निजी कंपनियों को दी गई है, जो मुनाफा कमाते हैं, नियमित नौकरियों को कैजुअल और ठेका नौकरियों में परिवर्तित करते हैं, पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करते हैं और अपने मुनाफे का विस्तार करने के लिए, जनता कोअंधाधुंध विस्थापित करते हैं।

तेल और गैस क्षेत्र को पहले के शासनकाल द्वारा रिलायंस जैसे बड़े कॉरपोरेटस् को पहले ही बेचा जा चुका है और मोदी सरकार इस राष्ट्री–विरोधी नीति को और आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। पिछले साल यह प्रस्तावित किया गया था कि ओएनजीसी में 18% हिस्सेदारी बेचकर सरकार को संभावित रूप से 41,000 करोड़ रुपये मिल जाऐंगे।

चूंकि मोदीनीतभाजपा सरकार ने 56,069.37 हेक्टेयर वन भूमि को लेकर परियोजनाओं के लिए बदल दिया है। इससे तसल्ली नहीं हुई, सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से वन भूमि को 'विकसित' करने के लिए नई वन नीति का प्रस्ताव करती है जिसका मतलब,अनिवार्य रूप से निजी ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स को वन भूमि को झपटलेना है। जंगलों के विनाश को चालू रखा जाएगा। निजी कंपनियों को नदियों और झीलों/तालाबों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी है ताकि वे उनका 'रखरखाव' कर सकें और उन्हे 'विकसित' कर सकें!

स्कूलों और अस्पतालों

प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8)का ही उदाहरण लें। सरकारी स्कूलों को आवश्यक धन से वंचित रखा जा रहा है। लाखों शिक्षकों की पद खाली रखी गए हैं। नतीजतन, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा करीब 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। निजी स्कूलों को खुला अवसर दिया जा रहा है; ऐसी 'शिक्षण दुकानों'को खोलने के लिए भारी छूट दी जा रही है। नतीजतन, 2010–11 और 2015–16 के बीच, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे इन कक्षाओं के छात्रों की संख्या में लगभग 10% की कमी आई, जबकि निजी स्कूलों में पढ़ रहे लोगों ने 26% की वृद्धि दर्ज की है! निजी स्कूलों में फीस आसमान छू रही है। लेकिन माता–पिता को अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि वे चाहते हैं कि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। उच्च शिक्षा में, सरकारी कॉलेजों में समानांतर गिरावट के साथ, निजी कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों का हिस्सा 2010–11 में 61% से बढ़कर 2015–16 में 67% हो गया है।

अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भी इसी तरह के नीचे रास्ते पर चले गए हैं। चिकित्सा परीक्षणों जैसी सेवाएं सरकारी अस्पतालों द्वारा निजी प्रयोगशालाओं में आउटसोर्स की जाती हैं। मरीजों को निजी प्रतिष्ठानों से महँगी दवाऐं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक ओर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर तृतीयक अस्पतालों की सरकारी प्रणाली,उपकरणों, बुनियादी ढांचे और कर्मियों (डॉक्टरों सहित) की कमी की शिकार है। दूसरी ओर, सस्ती भूमि सहित कई रियायतें प्रदान करके अधिक से अधिक निजी कॉरपोरेट अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वे अत्यधिक शुल्क वसूलते हैं और आम जनता की सीमा से पूरी तरह बाहर हैं। स्कूलों और कॉलेजों की तरह ही, लोगों को निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी रहती है।

मोदी सरकार ने वास्तव में एक कदम और आगे जाकर घोषित किया है कि वह देश को बीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए मजबूर करेगी। जनता को मुफ्त और व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की जिम्मेदारी को छोड़कर, सरकार इस बीमा आधारित मॉडल को बढ़ावा दे रही है। तो, इस योजना से लाभान्वित कौन होगा? स्वाभाविक रूप से, यह बीमा कम्पनियाँ है, जिनके खजाने में करोड़ों रुपए

आने हैं! कई निजी बीमा कम्पनियाँ स्वास्थ्य बीमा कारोबार में प्रवेश कर चुकी हैं। सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के सरकार के कर्तव्य का अनिवार्य रूप से निजीकरण करने का यह एक तरीका भी है।

रेलवे से लाल किले तक

मोदी सरकार को सलाह देने का काम करने वाले मक्कार दिमाग वाले, निजी कंपनियों के लिए लाभ पैदा करने के तरीके तैयार करने में व्यस्त हैं। वे पूरी तरह से जनता पर बोझ बढ़ाने या हमारे समृद्ध वास्तुशिल्प विरासत पर असर डालने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उदाहरण के लिए 23 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का निजीकरण किया जा रहा है। निजी कम्पनियाँ इन स्टेशनों का प्रबंधन करेंगी और बदले में उन्हें अपनी तरक्की के लिए, दुकानों और अन्य सेवाओं आदि का किराया वसूलने के वास्ते जगह का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार मिलेगा। सरकार ने पहले से ही रेलवे के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी है।

एक और उदाहरण लाल किले और ताजमहल जैसे स्मारकों के रखरखाव और प्रबंधन को निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले और तेलंगाना में गोलकोंडा किले को प्रमुख इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के आपत्तियों के बावजूद डालमिया व्यापार समूह को सौंप दिया गया है। 'राष्ट्रवाद' के बारे में इतना बोलने वाली सरकार क्या लाल किले का रखरखाव नहीं कर सकती, जो हमारे पहले स्वतंत्रता केयुद्ध का प्रतीक है औरजहाँ देश के प्रधान मंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं?

ये सभी कदम नवउदारवादी नीतियों का हिस्सा हैं; यही वह रास्ता है जो नवउदारवाद की ओर जाता है। इसे रोकना होगा। इसे रोका जा सकता है। केवल मजदूर वर्ग है, जो मेहनतकशों के अन्य वर्गों के साथ इसे रोक सकता है

हम सरकार से चाहते हैं कि

- निजीकरण बंद करो; सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करें; आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था विकसित करे
- सार्वजनिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाऐं; सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाऐं; सरकारी स्कूलों में बुनियादीढांचे में सुधार हो।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना;सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाऐं; बुनियादी ढांचे में सुधार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में सभी आवश्यक उपकरण, कर्मचारी, दवाऐं आदि प्रदान करें; देश के दूरस्थ कोनों में आदिवासियों सहित सभी के लिए सुलभ प्रभावी, समय पर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करें
- सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों सहित सभी विभागों में सभी रिक्त की पदों को भरें

यह संभव है। हमारे पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन हैं। सरकार को अपनी प्राथमिकताओं –जनता या कॉरपारेटस् को परिभाषित करना है? बड़े देशी–विदेशी कॉरपारेटसको हर साल 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की करों में एवं अन्य रियायतेंदेना बंद करो; अमीरों द्वारा न दिए, लेकिन कानूनी रूप से देय करों के 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह सुनिश्चित किया जाऐ;ज्यादातर बड़े कॉरपारेटस द्वारा न चुकाए गए12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण की वसूली सुनिश्चित करें, और इन बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

हालांकि, नवउदारवाद का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल,इन वैकल्पिक नीतियों को लागू करने में कभी गंभीर नहीं रहे हैं। यह केवल वामपंथी दल ही हैं जो इन मांगों को उठा रहे हैं, जो इन मांगों पर संघर्ष का

समर्थन कर रहे हैं, जो गंभीर बाधाओं के बावजूद भी उन राज्यों में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वे सत्ता में हैं।

आइए हम नवउदारवादी व्यवस्थाके शासन को परास्त करें; आइए मजदूर–समर्थक एवं जन–समर्थक वैकल्पिक नीतियों के लिए लड़ें। 5 सितंबर को संसद के समक्ष'मजदूर किसान संघर्ष रैली' इन नीतियों के खिलाफ हमारी आवाज उठाने के लिए है।

आइए एकजुट हों! संघर्ष करें!

ऐसी सरकारें नहीं जो 0.1% के लिए काम करें

उन नीतियों के लिए जो 99.9% के हित में हों